(घ) क्या छोटी सिगरेटों से उत्पादन पर सरकार द्वारा करों में छूट दिए जाने के, परिणामस्वरुप मध्य प्रदेश में 100 वर्ष पुराना परम्परागत बीडी उद्योग प्रभावित हुआ है, और

(ड) यदि हां तो क्या सरकार छोटी सिगेरटों पर दी गई इस छूट को समाप्त करेगी ताकि यह सुनिधित किया जा सके कि बीडी श्रमिकों वाले इन कुटीर उद्योगों को कोई नुकसान न पहुंचे जिससे लगभग 20 लाख जरुरतमंदों को जोकिका प्राप्त होती है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार राज्यों में बीड़ी कर्मकारों, के संबंध में न्युनतम मजदूरी की तुलनालक दरें निम्नानुसार है-

मध्य प्रदेश 30.18 रु. प्रति हजार बीडियां (1.10.96से)

उत्तर प्रदेश 35.00 रु. प्रति हजार बीडियां (3.1.94 से)

उड़ीसा 30.00 रु. प्रति हजार बीडियां (15.8.96 से)

बिहार 30.50 रु. प्रति हजार बीडियां (29.12.95 से)

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अन्य राज्यों में बीडी कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, मध्य प्रदेश में बीडी कर्मकारों की मजदूरी की न्यूनतम दर के समान ही है।

(घ) और (ड) 1993-94 से बीडियों से एकत्र किय गये उत्पाद शुल्क को कम किए जाने से बीडियों के उत्पादन में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है।

(ड) बीडी श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना

3544. श्री गोविन्दराम मिरी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन बीडी श्रमिकों के लिए, जो भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, सामूहिक बीमा योजना शुरु की है जिसके अन्तर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को तीन से पच्चीस हजार रुपए तक की राशि का मुआवजा दिया जाता है।

(ख) क्या बीडी श्रमिकों को पहचान पत्र जारी न किए जाने के कारण ऐसे लाखों श्रमिकों को भारतीय जीवन बीमा निगम, कल्याण आयोग और श्रम मंत्रालय द्वारा जान बूझकर उपर्युक्त लाभ से वंचित रखा गया है और,

(ग) यदि हो, तो सरकार द्वारा उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

(ख) और (ग) जी, नहीं। वस्तुत: बीडी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 41 के अन्तर्गत बीडी कर्मकारों को परिचय पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व नियोजक का है। तथापि, चूंकि नियोजक आमतौर पर इस दायित्व को पुरा करने के लिए आगे नहीं आते हैं, इसलिए श्रम मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठनों ने प्राथमिकता आधार पर बीडी कर्मकारों को परिचम पत्र जारी करने का कार्य हाथ में लिया है और प्रत्येक औपधालय द्वारा 250 परिचम पत्र जारी करने का मासिक लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों से कल्याण आयुक्त के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाने का भी अनुरोध किया गया है ताकि सभी बीडी कर्मकारों की ठीक ढंग से पहचान की जा सके और उन्हें समूह बीमा याजना एवं अन्य कल्याण योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए परिचय पत्र जारी किया जा सके। इसके परिणआमस्वरुप, देश में अनुमानत:43.63 लाख बीड़ी कर्मकारों में से अब तर 32,92,974 बीड़ी कर्मकारों को परिचय पत्र जारी किए जा चुके हैं।

Action against Delhi-Based Japanese Companies to Enforce Labour laws

3545. SHRI MOOLCHAND MEENA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some of- the Delhi based Japanese Companies, including Sumitomo Corporation and the Mutsui Corporation are not paying minimum wages to Indian Security guards and office boys/ messengers employed by them;

(b) if so, the action taken against these companies to enforce the labour laws;

(c) whether the Japanese officers observe racial practice and discrimination against their Indian employees;